RNI No#MPBIL/2013/49052

INVESTMENT AVENUES®

इन्वेस्टमेंट ऐवेन्यूस

भोपाल, शनिवार 13 दिसंबर से 19 दिसंबर 2025 | भोपाल , मध्यप्रदेश से प्रकाशित | वर्ष- 13 | अंक-70 | पृष्ठ- 8 | मूल्य- रु. 5 /-

कृषि वृद्धि FY26 में 4% रहने का अनुमान: नीति आयोग सदस्य रमेश चंद्र; शिवराज सिंह चौहान ने मिट्टी क्षरण रोकने के लिए संतुलित उर्वरक उपयोग पर जोर दिया

मिट्टी की उर्वरता बचाने और उत्पादकता बढ़ाने की जरूरत; नीति आयोग ने चेतावनी दी, असंतुलित उर्वरक से दीर्घकालिक नुकसान

नई दिल्ली: नीति आयोग के सदस्य (कृषि) रमेश चंद्र ने अनुमान जताया है कि वित्त वर्ष 2025-26 में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 4% रह सकती है, जो पिछले वर्षों की तुलना में कम है। उन्होंने कहा कि असंतुलित उर्वरक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता घट रही है, जिससे उत्पादकता पर दीर्घकालिक असर पड़ रहा है। चंद्र ने कृषि सम्मेलन में चेतावनी दी कि यदि उर्वरक उपयोग का संतुलन नहीं बनाया गया तो कृषि विकास दर और प्रभावित हो सकती है।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी मिट्टी क्षरण रोकने के लिए संतुलित उर्वरक उपयोग पर जोर दिया। उन्होंने किसानों से अपील की कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश (NPK) का अनुपात बनाए रखें और जैविक खादों का उपयोग बढ़ाएं। चौहान ने कहा, असंतुलित उर्वरक से मिट्टी बंजर हो रही है। हमें मिट्टी की सेहत बचानी होगी, तभी खाद्यान्न उत्पादन बढ़ेगा और किसान समृद्ध होंगे।

नीति आयोग के अनुसार, FY25 में कृषि वृद्धि 4.5% रही, लेकिन FY26 में मौसम, उर्वरक उपलब्धता और वैश्विक कीमतों से चुनौतियां हैं। उर्वरक सब्सिडी पर 1.7 लाख करोड़ का बोझ है, फिर भी NPK अनुपात बिगड़ा हुआ है। चौहान ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड और जैविक खेती को बढ़ावा देने की योजना बताई। विशेषज्ञों का मानना है कि संतुलित उपयोग से उत्पादकता 10-15% बढ़ सकती है। सरकार PM-KISAN और फसल बीमा के साथ मिट्टी संरक्षण पर फोकस कर रही है। यह प्रयास 'कृषि विकसित भारत' के लक्ष्य को मजबूत करेगा।

लोन सस्ते होंगे: RBI के रेट कट के बाद PNB, HDFC समेत 6 बैंकों ने घटाईं होम लोन ब्याज दरें

20 लाख के 20 साल लोन पर 74 हजार की बचत, EMI में 600-800 रुपये मासिक राहत; बैंक ऑफ महाराष्ट्र की दर सबसे कम 7.10%

मुंबई: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के रेपो रेट में 0.25% कटौती के बाद देश के प्रमुख बैंकों ने होम लोन की ब्याज दरें घटा दी हैं। पंजाब नेशनल बैंक (PNB), HDFC बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB), इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया (BoI) और बैंक ऑफ महाराष्ट्र समेत 6 बड़े बैंकों ने 0.05% से 0.25% तक की कटौती की है। इससे नए उधारकर्ताओं को सस्ते लोन का फायदा मिलेगा, जबकि पुराने ग्राहक EMI रीसेट कर बचत कर सकेंगे।

PNB ने अपनी रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट (RLLR) को 8.85% से घटाकर 8.60% कर दिया। HDFC बैंक ने होम लोन दरें 7.35% से शुरू करने की घोषणा की। BoB ने MCLR 0.25% घटाई, जबकि BoI ने 7.90% की दर तय की। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने सबसे सस्ती दर 7.10% ऑफर की, जो नए ग्राहकों के लिए आकर्षक है। इंडियन बैंक ने भी 0.25% कटौती की। ये दरें 9 दिसंबर से लागू हो गईं।उदाहरण के तौर पर, 20 लाख रुपये के 20 साल के होम लोन पर 8.5% से 7.25% दर पर EMI 600-800 रुपये मासिक कम हो जाएगी, जिससे कुल ब्याज बचत करीब 74,000 रुपये होगी। RBI के 5 दिसंबर के फैसले से बैंकों की फंडिंग कॉस्ट घटी, जिसका लाभ ग्राहकों को मिल रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम आवास क्षेत्र को गति देगा, जहां 2025 में 1.2 लाख करोड़ के लोन वितरित हुए।

हालांकि, क्रेडिट स्कोर, LTV रेशियो और टेन्योर पर दरें निर्भर करेंगी। ग्राहक बैंकों से प्री-पेमेंट पेनल्टी की जानकारी लें। FY26 में 6.5% विकास लक्ष्य के बीच यह राहत मध्यम वर्ग के लिए सकारात्मक है। शेयर बाजार में बैंकिंग स्टॉक्स 1-2% चढ़े।

FTA में ऑटो कंपोनेंट्स पर ड्यूटी कटौती सावधानी से: MSMEs की सुरक्षा जरूरी, एसोचैम का आह्वान

EU व्यापार समझौते में 'कैलिब्रेटेड' रियायतें, चरणबद्ध समयसीमा और सुरक्षा उपाय; एसोचैम प्रेसिडेंट ने चेतावनी दी, MSMEs पर बुरा असर न हो

नई दिल्ली: एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम) ने भारत-यूरोपीय संघ (EU) मुक्त व्यापार समझौते (FTA) में ऑटो कंपोनेंट्स पर आयात शुल्क कटौती को सावधानीपूर्वक अपनाने की सलाह दी है। एसोचैम के प्रेसिडेंट निर्मल कुमार मिंडा ने कहा कि EU के साथ व्यापार समझौते में 'ब्लैकेट रिडक्शन' से घरेलू निर्माताओं, खासकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को नुकसान हो सकता है। उन्होंने चरणबद्ध समयसीमा, पारस्परिकता और सुरक्षा उपायों से जुड़ी 'कैलिब्रेटेड' रियायतों की मांग की है।

मिंडा ने पीटीआई को दिए ईमेल साक्षात्कार में कहा, EU कंपोनेंट्स अक्सर बड़े पैमाने, ऑटोमेशन और सब्सिडी के साथ आते हैं। इसलिए, कटौती को भारत की लंबी अवधि की रणनीतिक हितों के साथ संतुलित करना होगा।" भारत और 27-राष्ट्र EU ब्लॉक 2007 से FTA पर बातचीत कर रहे हैं। 9 दिसंबर को उच्च स्तरीय बैठक हुई, जहां EU ने ऑटोमोबाइल और कंपोनेंट्स पर शुल्क छूट मांगी। ऑटो कंपोनेंट्स सेक्टर, जो PLI योजना के तहत प्रगति कर रहा है, को चिंता है कि अंधाधुंध कटौती हालिया उपलब्धियों को प्रभावित कर सकती है।

मिंडा ने कहा, किसी भी छूट को स्पष्ट पारस्परिकता, चरणबद्ध समयसीमा और सुरक्षा उपायों से जोड़ा जाना चाहिए, ताकि भारत का विनिर्माण आधार बढ़ता रहे। उन्होंने नई व्यापार समझौतों से बाजार पहुंच सुधारने और लंबी अवधि के निवेश को बढ़ावा मिलने का उल्लेख किया। कई सेक्टरों में निर्यात में वृद्धि हुई है, लेकिन MSMEs को इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए समर्थन की जरूरत है।

भारत का ऑटो कंपोनेंट्स निर्यात FY25 में 20% बढ़कर 18.5 अरब डॉलर हो गया। MSMEs इस सेक्टर का 60% हिस्सा हैं। एसोचैम ने सुझाव दिया कि EV, प्रिसिजन इंजीनियरिंग और लाइटवेट मटेरियल्स जैसे क्षेत्रों में EU के साथ सहयोग बढ़ाया जाए। विशेषज्ञों का मानना है कि सावधानीपूर्ण दृष्टिकोण से भारत वैश्विक मूल्य श्रृंखला में मजबूत होगा। यह चेतावनी FTA वार्ता को संतुलित बनाने में मदद करेगी।

भारतीय तेल निगम ने जनवरी डिलीवरी के लिए LNG कार्गो की मांग की: ऊर्जा सुरक्षा के लिए वैकल्पिक स्रोतों पर फोकस

20 जनवरी को दाहेज टर्मिनल पर डिलीवरी, 9 दिसंबर तक टेंडर प्रक्रिया; अमेरिकी प्रतिबंधों से रूसी गैस पर निर्भरता कम करने का प्रयास

मुंबई: इंडियन ऑइल कारपोरेशन (IOC) ने जनवरी डिलीवरी के लिए लिक्विड नेचुरल गैस (LNG) कार्गो की खरीद के लिए टेंडर जारी किया है। उद्योग स्रोतों के अनुसार, यह कार्गो 20 जनवरी को गुजरात के दाहेज टर्मिनल पर पहुंचेगा। टेंडर प्रक्रिया 9 दिसंबर को समाप्त होगी। यह कदम अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण रूसी गैस आपूर्ति में संभावित कमी से निपटने के लिए उठाया गया है।

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, IOC ने जनवरी के लिए LNG कार्गो की मांग की है, जो भारत की ऊर्जा खरीदारी प्रयासों को दर्शाता है। भारत, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा LNG आयातक, रूस से सस्ती गैस पर निर्भर हो गया था, लेकिन रोसनेफ्ट और लुकोइल जैसे रूसी दिग्गजों पर अमेरिकी प्रतिबंधों से आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो रही है। IOC, जो देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी कंपनी है, ने हाल ही में दाहेज टर्मिनल पर क्षमता बढ़ाई है। FY25 में IOC का LNG आयात 20% बढ़ा था, लेकिन अब वैकल्पिक स्रोतों पर फोकस है।

स्रोतों ने बताया कि IOC ने दाहेज टर्मिनल के लिए कार्गो की मांग की है, जो गुजरात में प्रमुख LNG आयात केंद्र है। यह कदम भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगा, जहां प्राकृतिक गैस कुल ऊर्जा का 6.5% है। सरकार का लक्ष्य 2030 तक गैस हिस्सेदारी 15% तक ले जाना है। विशेषज्ञों का मानना है कि LNG आयात बढ़ाने से घरेलू उत्पादन को गति मिलेगी। IOC के शेयर 1.2% चढ़े। यह प्रयास आत्मनिर्भर ऊर्जा को बढ़ावा देगा।

RBI Governor Urges Banks to Slash Costs and Harness Tech in Easing Cycle

Sanjay Malhotra Calls for Efficiency Gains as Repo Rate Hits 5.25%; Focus on Digital Lending, Cybersecurity, and Lower Operating Expenses

Mumbai: Reserve Bank of India Governor Sanjay Malhotra has exhorted banks to leverage technology and prune operating costs to maintain healthy margins amid the ongoing monetary easing cycle. Speaking at the FIBAC 2025 banking conclave on Thursday, Malhotra said the cumulative 125 bps repo rate cut since February 2025 has compressed net interest margins (NIMs), making efficiency paramount.

With policy rates trending lower, banks must accelerate digital transformation and rationalise branch networks to protect profitability, Malhotra stated. He highlighted the need for AI-driven credit assessment, blockchain for faster settlements, and robust cybersecurity to counter rising digital fraud, which surged 300% in FY25.

Malhotra praised public sector banks for improving cost-to-income ratios to below 50% but urged private peers to follow suit. He also flagged the importance of co-lending models with fintechs to expand reach while sharing risks. Technology is no longer optional, it is the backbone of inclusive and resilient banking, he emphasised.

The Governor's remarks come as banks face pressure from slowing credit growth (12% YoY) and rising NPAs in unsecured retail. With another potential 25 bps cut expected in February 2026, analysts forecast NIM compression of 10–15 bps unless offset by efficiency gains.

Shares of major banks rose 1–2% post the speech, reflecting optimism over regulatory support for digital initiatives. As India targets a $5 trillion economy, Malhotra's call underscores the sector's pivot toward tech-led, cost-efficient growth.

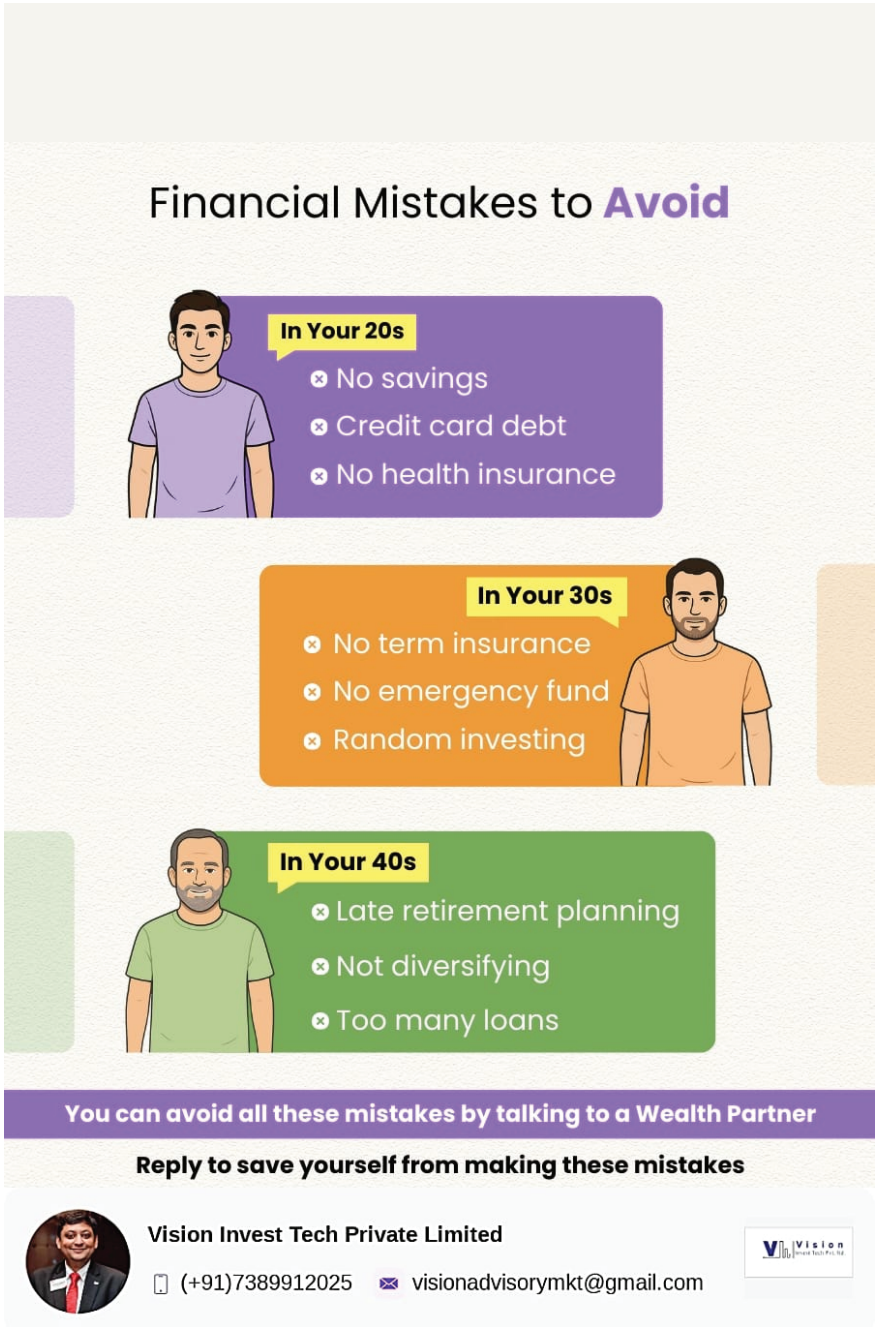

Sh. Pradeep Karambelkar
Founder & Editor

Dr. Irshad Ahmad Khan
Sub-Editor

Sh. Pushpendra Singh
Marketing Officer

SIP Revolution: How India is Building a Nation of Long-Term Investors

India is witnessing a major shift in the way people save and invest. For decades, Indians preferred gold, real estate, and bank deposits as the safest options for their money. But today, a silent revolution is taking place. Systematic Investment Plans, commonly known as SIPs, have transformed investing from a risky activity into a disciplined habit for millions of families. This growing SIP culture is building a new generation of long-term investors and strengthening India's financial ecosystem.

SIPs allow individuals to invest a fixed amount regularly: monthly, quarterly, or even weekly into mutual funds. This simple method removes the fear of timing the market and helps investors benefit from compounding. More importantly, SIPs suit the Indian mindset of gradual, steady saving. Just like recurring deposits, SIPs make investing easier for common people by automating the process and reducing emotional decision-making.

The rise of SIPs has been extraordinary. Monthly SIP inflows have touched record highs, crossing ₹20,000 crore, showing that Indian households are embracing equity markets with confidence.

Small-town participation has surged as digital platforms, mobile apps, and online KYC have made investing convenient and paperless. Even first-time investors now understand that long-term investing is better than reacting to short-term market ups and downs.

One key reason behind the SIP revolution is financial awareness. Campaigns by mutual fund companies, AMFI, and financial influencers have educated people about the benefits of long-term investment. The message "Mutual Funds Sahi Hai" has become one of the most successful financial literacy slogans in the country. As more Indians learn about inflation, compounding, and wealth creation, they realise that traditional savings alone cannot meet future goals like children's education, retirement, or buying a home.

Another factor driving SIP adoption is India's strong economic growth. With rising incomes, urbanisation, and digital banking, more families are able to save and invest. Younger Indians, especially those in their 20s and 30s, are starting SIPs early, giving them a long runway for wealth creation. This young investing population is likely to support the stock market for decades, providing stability and depth to India's capital markets.

SIPs also help investors stay disciplined during market volatility. Instead of panicking during market corrections, SIP investors continue investing automatically.

This helps them buy more units when the market is low and fewer when it is high, abenefit known as rupee-cost averaging. Over the years, this reduces the impact of market fluctuations and improves long-term returns. Many financial planners call SIPs the most practical way for common people to participate in India's economic growth.

The SIP revolution is also strengthening India's financial markets. With consistent monthly inflows, domestic investors are now a counterbalance to foreign investors, whose buying and selling earlier caused sharp market movements. Steady SIP money provides long-term stability to the stock market and supports Indian companies in raising funds for expansion.

India is on its way to becoming a nation of disciplined, long-term wealth creators. As more households adopt SIPs, long-term financial security becomes more achievable for the average citizen. The SIP revolution is not just changing investment habits; it is helping build a stronger, more financially confident India.

Dr. Irshad Ahmod Khan
Sub-Editor

पीएम सूर्य घर योजना: दिसंबर 2025 तक 24 लाख घरों में रूफटॉप सोलर की चमक

1 करोड़ लक्ष्य का 24% हासिल, 53.54 लाख आवेदन; 28.8 मिलियन टन CO2 कटौती, 17 लाख नौकरियां सृजित होंगी

भोपाल: प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (PMSG: MBY) ने भारत के हरित ऊर्जा क्रांति को नई गति दी है। दिसंबर 2025 तक लगभग 24 लाख घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित हो चुके हैं, जो 1 करोड़ घरों के राष्ट्रीय लक्ष्य का 24% है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद नायक ने राज्यसभा में बताया कि 3 दिसंबर 2025 तक राष्ट्रीय पोर्टल पर 53.54 लाख आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जबकि 19.17 लाख सिस्टम सफलतापूर्वक इंस्टॉल हो गए हैं।

यह योजना FY 2026-27 तक 1 करोड़ घरों को कवर करने का लक्ष्य रखती है, जिसमें 75,021 करोड़ रुपये का बजट है। प्रत्येक घर को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी, जो बिजली बिल को शून्य कर देगी। गुजरात (2.28 लाख इंस्टॉलेशन) और महाराष्ट्र (2.35 लाख) शीर्ष राज्य हैं, जबकि उत्तर प्रदेश (1.21 लाख) तीसरे स्थान पर है। योजना से 30 GW सोलर क्षमता जुड़ेगी, जो 25 वर्षों में 28.8 मिलियन टन CO2 उत्सर्जन कम करेगी। साथ ही, 17 लाख प्रत्यक्ष नौकरियां (निर्माण, लॉजिस्टिक्स, स्थापना और रखरखाव) सृजित होंगी।

मंत्री नायक ने कहा, "यह योजना निम्न-मध्यम आय वर्ग को सशक्त बनाएगी। सब्सिडी, कोलेटरल-फ्री लोन (7% ब्याज) और एकल खिड़की आवेदन प्रक्रिया से अपनाने को आसान बनाया गया है।" FY 2025-26 में अतिरिक्त 35 लाख घरों को कवर करने का लक्ष्य है। योजना का पोर्टल सरल पंजीकरण, वेंडर चयन और सब्सिडी वितरण सुनिश्चित करता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह भारत के नेट-जीरो लक्ष्य (2070) को गति देगी। ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर गांवों का विकास मॉडल बनेगा। आवेदन प्रक्रिया में 9 चरणों का पालन करें: पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन से लेकर इंस्टॉलेशन तक। यह पहल हरित क्रांति का प्रतीक है, जो लाखों परिवारों को ऊर्जा स्वतंत्रता देगी।

Abu Dhabi's IHC Secures CCI Approval for $1 Bn Stake in Sammaan Capital

43.46% Acquisition through Avenir Investment Marks Major Foreign Entry into Indian NBFC; Deal to Bolster Lending and AI-Driven Credit Solutions

Mumbai: In a significant boost for India's financial services sector, the Competition Commission of India (CCI) has approved Abu Dhabi-based International Holding Company's (IHC) $1 billion (Rs 8,850 crore) acquisition of a 43.46% stake in Sammaan Capital Ltd, a leading non-banking financial company (NBFC). The nod, announced on December 9, clears the path for IHC's affiliate, Avenir Investment RSC Ltd, to become the new promoter of the RBI-registered upper-layer NBFC.

The deal, first announced in October 2025, involves issuing preferential shares to Avenir, diluting existing shareholders' stake from 98.25% to 57.74%. It will trigger a mandatory open offer for an additional 26% from public shareholders. Sammaan Capital, formerly Indiabulls Housing Finance, operates a network of 220 branches across 150+ towns, focusing on retail and wholesale lending, MSME loans, lease rental discounting, asset management, and insurance distribution. The infusion will fund AI-enhanced lending and credit solutions, aiming to expand its $10 billion loan book.

This USD 1 billion investment reaffirms our commitment to supporting Sammaan Capital in its next phase of development, including the adoption of AI to enhance lending and credit solutions, and to contributing meaningfully to India's financial ecosystem," said Syed Basar Shueb, CEO of IHC. The transaction, notified under Section 5(a) of the Competition Act, poses no appreciable adverse effect on competition, per CCI's assessment. Sammaan Capital's shares surged 9% to Rs 154.35 on BSE following the approval, reflecting market optimism. The lender reported FY25 revenue of Rs 63,910 crore and net profit of Rs 1,226 crore, dominating 19% of India's Rs 2 lakh crore edible oils market-no, wait, that's incorrect; actually, as an NBFC, it excels in mortgage and MSME financing.

This marks IHC's strategic foray into Indian fintech, leveraging its diversified portfolio in finance, healthcare, and real estate. For Sammaan, the capital will accelerate growth amid RBI's push for digital lending. Analysts forecast a 20-25% revenue uptick post-deal, positioning the NBFC as a key player in a $500 billion credit market. As foreign investments flow into India's BFSI sector, FDI inflows hit $18.6 billion in H1 FY26, this approval underscores regulatory support for consolidation and innovation.

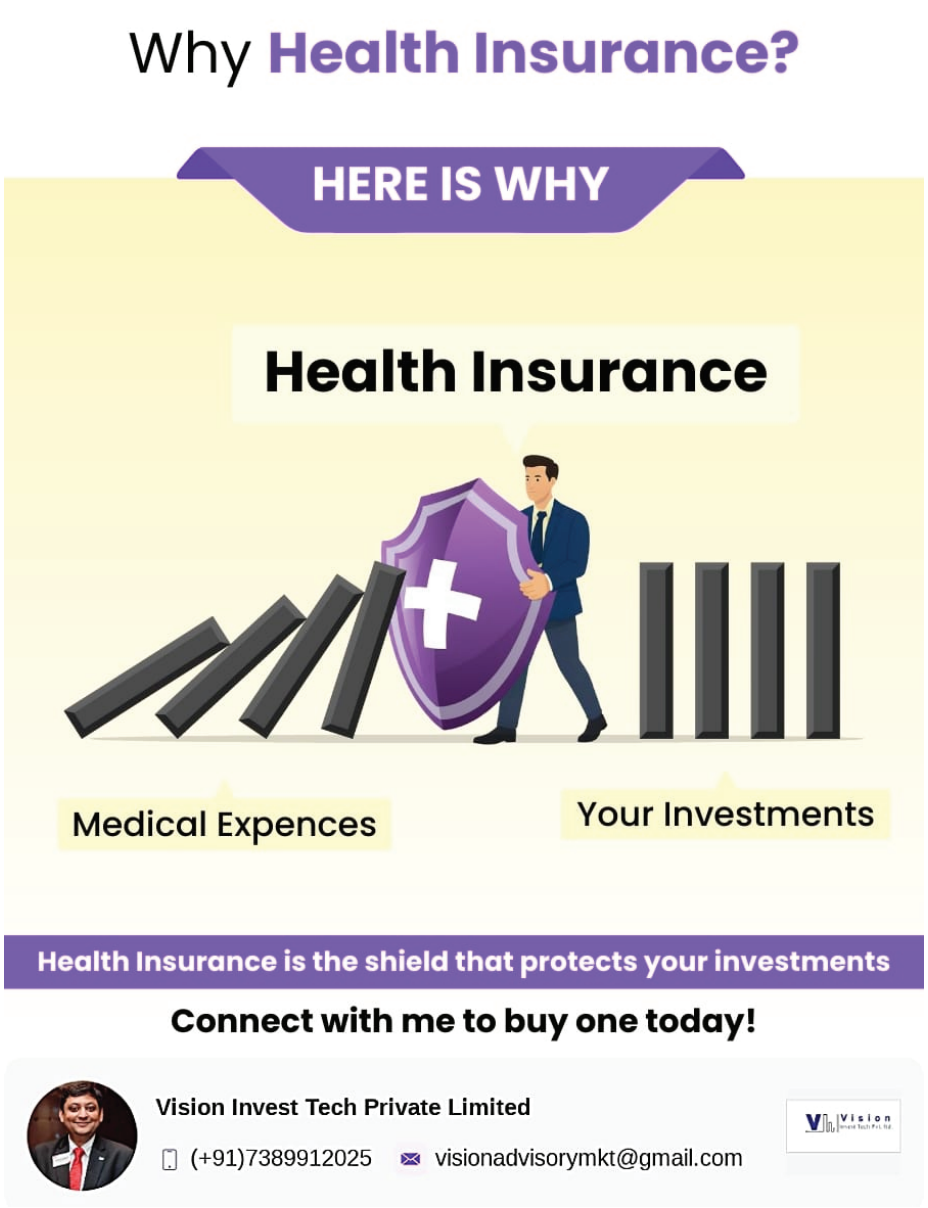

Insurers Push for FASTag Issuance Rights to Expand Digital Reach

IRDAI Seeks Government Approval for General Insurers to Sell FASTags; Move to Leverage 80,000+ Branches and Boost Non-Motor Revenue

Mumbai: In a bid to diversify revenue streams and deepen digital penetration, general insurance companies have approached the Centre for permission to issue FASTag stickers, the electronic toll collection devices mandatory on national highways. The Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) has formally recommended the proposal to the Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH), sources confirmed on Tuesday.

Currently, only 34 banks and authorised agencies like IHMCL can issue FASTags, with over 90 million active tags generating Rs 60,000 crore annually in toll revenue. Insurers argue their vast network 80,000+ branches and 5 lakh agents can accelerate adoption in rural and semi-urban areas, where FASTag penetration lags at 65%. “Bundling FASTags with motor insurance policies will enhance customer convenience and create a new non-risk revenue stream,” said a senior IRDAI official.

The move aligns with the government's One Nation, One FASTag vision and digital payment push. Industry estimates suggest insurers could capture 10–15% market share within two years, adding Rs 1,500–2,000 crore in fee-based income. Companies like Bajaj Allianz and ICICI Lombard have piloted similar digital offerings.

MoRTH is reviewing the proposal, with a decision expected by March 2026. Analysts see it as a win-win: faster toll compliance for NHAI and diversified earnings for insurers amid rising claims ratios. Shares of listed insurers rose 1–3% on the news, reflecting optimism over ancillary revenue potential.

Electronics Sector Urges Govt to Approve China JVs with 26% Stake Cap

Industry Bodies Push for Automatic Route to Attract FDI and Boost Component Manufacturing; Exceptions for US/EU Relocations Amid Tech Transfer Norms

New Delhi: Indian electronics industry leaders have urged the Centre to allow joint ventures (JVs) with Chinese companies on an automatic route, capped at a 26% minority stake, to accelerate advanced component manufacturing and attract foreign investment. Representations from bodies like the Confederation of Indian Industry (CII) and India Electronics & Semiconductor Association, reviewed by ET, emphasize the need for a fixed guideline to replace case-by-case scrutiny under Press Note 3.

The proposal comes amid growing demand for local production of critical parts like display modules, camera sensors, PCBs, and lithium cells, vital for smartphones, EVs, and IoT devices. A structured 26% cap would unleash FDI flows while safeguarding national interests, an industry executive told ET. Dixon Technologies recently secured MeitY approval for its JV with China's Longcheer Intelligence, where Dixon holds 74% and Longcheer 26%, focusing on R&D and manufacturing of intelligent products.

Government sources indicate openness to tweaking rules for US or European firms relocating from China, potentially allowing up to 49% Chinese supplier stakes as exceptions, evaluated individually. This aligns with 'China Plus One' strategies, but caution persists due to Beijing's policy inconsistencies on tech transfers. Firms like Micromax, Zetwerk, and Syrma SGS are eyeing collaborations with Chinese peers in display and IC chipsets.

The Electronics Components Manufacturing Scheme (ECMS) under PLI incentivizes such JVs, targeting $300 billion exports by 2030. However, delays in approvals—such as Hisense's stalled 26% acquisition in Epack Durable and Bharti Group's Haier India bid—frustrate progress. "Clear guidelines are essential to avoid Vietnam-like Chinese dominance," warned a CII official.

As India aims for 10% global electronics market share, calibrated JVs could bridge tech gaps without compromising security. The government is deliberating, with decisions expected in Q1 2026.

Suzlon Unveils Ambitious Plan for Three AI-Enabled Smart Blade Factories

Gujarat and Karnataka Sites to Boost 6.2 GW Order Book Execution; Expansion Marks India's Largest Wind Manufacturing Network

Mumbai: In a bold move to fortify India's renewable energy ecosystem, Suzlon Energy Ltd has announced plans to commission three new AI-enabled smart blade manufacturing factories, expanding its nationwide footprint to 20 facilities. The initiative, revealed on Thursday, aims to accelerate execution of the company's 6.2-gigawatt (GW) order book, reduce logistics timelines, and integrate cutting-edge digital technologies for superior productivity and quality.

Two factories will be established in Gujarat and Karnataka key wind energy corridors while the location for the third is under evaluation. Funded through Suzlon's annual capex of Rs 500-550 crore from internal accruals, these units will be positioned near upcoming wind project clusters to streamline transportation of large turbine components. This expansion is a cornerstone of our strategy to drive sustainable growth and meet the surging demand for indigenised wind equipment, said Girish Tanti, Co-Founder, Suzlon Group.

The smart factories will feature AI-driven vision systems for instant defect detection, digital quality platforms like AskCQMS, and the SAFER safety app for enhanced workplace assurance. Automation, robotics, and advanced monitoring will boost blade quality, productivity, and safety from day one. Currently, Suzlon operates five blade factories in Jaisalmer, Bhuj, Ratlam, Dhule, and Anantapur, with a total manufacturing capacity of 4.5 GW across 17 facilities a 50% increase from FY24.

Group CEO J.P. Chalasani highlighted the project's alignment with India's 500 GW non-fossil capacity target by 2030. "With only 4% of India's 1,164 GW technical wind potential utilised, we're poised for double-digit annual installations, he noted. The expansion supports Suzlon's three strategic pillars: technology and manufacturing, project development, and long-term services like repowering, which could extend turbine life by 3-7 years and double power generation at older sites.

Suzlon, which services nearly one-third of India's 50 GW operational wind fleet, is urging customers to finalise sites two years ahead to shift from 6 GW to double-digit annual growth. The company remains unfazed by competition from global players like China's Envision, emphasising its lifetime O&M model for unmatched value.

Shares of Suzlon rose 2.5% to Rs 85 on BSE, reflecting investor confidence in its turnaround and green push. As India accelerates renewable adoption, Suzlon's AI-led factories could unlock Rs 10,000 crore in new orders, fostering jobs and innovation in the sector.

Adani Green Embraces TNFD Framework: Pioneering Nature-Positive Renewable Energy in India

World's Largest Renewable Developer Integrates Biodiversity Disclosures; Targets No Net Loss by 2030 with 28 million Tree Planting Initiative

Mumbai: Adani Green Energy Ltd (AGEL), India's largest renewable energy company, has integrated the Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) framework into its core sustainability strategy, marking a significant shift toward nature-positive development. Announced on Monday, this move positions AGEL as a leader among global renewables firms, embedding biodiversity considerations into strategic decision-making to balance clean energy expansion with ecological restoration.

The TNFD, a science-based initiative backed by the United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI), UNDP, World Wildlife Fund (WWF), and Global Canopy, provides a structured approach to identify, assess, manage, and disclose nature-related dependencies, impacts, risks, and opportunities. By adopting it, AGEL transitions from traditional ESG compliance to an integrated model that ensures ecological well-being advances alongside its ambitious growth targets.

AGEL, with an operational portfolio exceeding 16.5 GW across 12 states the largest in India has committed to achieving 'No Net Loss of Biodiversity by 2030. This includes planting 27.86 million trees and expanding its renewable footprint, such as the 30 GW Khavda project in Gujarat, spanning 538 square kilometers of barren land. "Nature is central to our growth story. By mainstreaming TNFD principles, we are building resilient ecosystems alongside renewable infrastructure," said Ashish Khanna, CEO, AGEL.

The company began company-wide assessments in FY24 to map nature-related factors across all sites, even before joining the TNFD Adopters group. This proactive stance supports India's climate leadership and global conservation priorities. AGEL's operational sites are already certified water-positive, single-use plastic-free, and zero waste-to-landfill, underscoring its holistic approach.

Following Adani Cement and Adani Ports, AGEL's adoption highlights the group's commitment to biodiversity amid rapid scaling. With India's renewable capacity target of 500 GW by 2030, such frameworks could mitigate environmental risks in solar and wind projects.

Analysts praise the move as a blueprint for sustainable growth, potentially enhancing investor appeal in green bonds. Shares of AGEL rose 1.5% to Rs 1,045 on BSE, reflecting market optimism for its nature-integrated vision.

कल्पतरु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल ने 2,003 करोड़ के ऑर्डर हासिल किए: वैश्विक विस्तार को नई गति

अंतरराष्ट्रीय T&D प्रोजेक्ट्स में मजबूती, भारत में B&F सेगमेंट में उछाल; FY26 ऑर्डर बुक अब 15,000 करोड़ पार

मुंबई : इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन (EPC) क्षेत्र की प्रमुख कंपनी कल्पतरु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड (KPIL) ने 2,003 करोड़ रुपये के नए ऑर्डर हासिल किए हैं। इनमें अंतरराष्ट्रीय ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन (T&D) प्रोजेक्ट्स और भारत में बिल्डिंग्स एंड फैक्ट्रीज (B&F) सेगमेंट शामिल हैं। कंपनी ने मंगलवार को बीएसई फाइलिंग में इसकी जानकारी दी, जो FY26 की शुरुआत में मजबूत मांग का संकेत देती है।

KPIL के MD और CEO मनीष मोहन ने कहा, ये ऑर्डर हमारी वैश्विक क्षमता और विविधीकरण को दर्शाते हैं। T&D में अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स से राजस्व बढ़ेगा, जबकि B&F सेगमेंट घरेलू बाजार को मजबूत करेगा। ऑर्डर में अंतरराष्ट्रीय T&D का मूल्य 1,200 करोड़ रुपये है, जो मध्य पूर्व और अफ्रीका में हाई-वोल्टेज लाइनों और सबस्टेशनों के निर्माण से जुड़ा है। भारत में B&F ऑर्डर 803 करोड़ के हैं, जो औद्योगिक इमारतों और फैक्ट्रियों के विकास पर केंद्रित हैं।

कंपनी का FY26 ऑर्डर बुक अब लगभग 15,000 करोड़ रुपये का हो गया है, जो पिछले वर्ष से 25% अधिक है। T&D सेगमेंट का योगदान 60% से ऊपर है, जबकि B&F और अन्य क्षेत्रों में वृद्धि दर्ज हुई। KPIL, जो 75 देशों में सक्रिय है, ने हाल ही में H1 FY26 में 9% राजस्व वृद्धि दर्ज की। कंपनी का फोकस सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स शामिल हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि ये ऑर्डर भारत की इंफ्रा डिमांड और वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन को दर्शाते हैं। KPIL का शेयर बाजार में 3% उछाल आया। यह कदम कंपनी को EPC सेक्टर में अग्रणी बनाएगा।

वेदांता राजस्थान में 1 लाख करोड़ निवेश करेगी: तेल-गैस, जिंक और एल्युमीनियम उत्पादन में भारी

2030 तक 50% तेल उत्पादन और जिंक में दोगुना लक्ष्य; 1 लाख नौकरियां, राज्य को GDP में 5% योगदान

जयपुर: अनिल अग्रवाल की अगुवाई वाली वेदांता ग्रुप ने राजस्थान में अगले 5 वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपये का मेगा निवेश करने की घोषणा की है। यह निवेश तेल-गैस, जिंक, लेड, सिल्वर और एल्युमीनियम उत्पादन को बढ़ाने पर केंद्रित होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में राइजिंग राजस्थान' समिट में वेदांता चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने कहा, राजस्थान हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। हम यहां तेल उत्पादन को 50% और जिंक उत्पादन को दोगुना करना चाहते हैं। वेदांता का यह निवेश राज्य की GDP में 5% योगदान देगा और 1 लाख नई नौकरियां सृजित करेगा।

वेदांता की सहायक कंपनी केयर्न ऑयल एंड गैस राजस्थान में 60% तेल उत्पादन करती है। कंपनी बाड़मेर रिफाइनरी की क्षमता 2.3 लाख बैरल से बढ़ाकर 4 लाख बैरल प्रतिदिन करने की योजना बना रही है। जावर में जिंक इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी जिंक माइन है, जिसकी क्षमता 2 मिलियन टन तक ले जाई जाएगी। अग्रवाल ने कहा, हम राजस्थान को विश्व स्तरीय खनन हब बनाएंगे।

मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा, वेदांता का निवेश राज्य को औद्योगिक क्रांति देगा। हम हर संभव सहायता देंगे। यह निवेश आत्मनिर्भर भारत और राजस्थान के 2030 तक 350 अरब डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को मजबूत करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे रोजगार और राजस्व में भारी वृद्धि होगी। वेदांता के शेयर 2% चढ़े।

टाटा स्टील थ्रिवेनी पेलेट्स में बहुमत हिस्सेदारी खरीदेगी: कच्चे माल की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने का कदम

51% तक अधिग्रहण, 2027 तक पूरा सौदा; ओडिशा के 4 MTPA पेलेट प्लांट से लौह अयस्क की निर्बाध आपूर्ति, लागत में 5-7% बचत

जमशेदपुर: टाटा स्टील लिमिटेड ने ओडिशा स्थित थ्रिवेनी पेलेट्स प्राइवेट लिमिटेड में बहुमत हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। कंपनी 2,100 करोड़ रुपये में 67% स्टेक अधिग्रहण करेगी, जिससे उसकी कच्चे माल आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होगी। यह सौदा टाटा स्टील की लंबी अवधि की रणनीति का हिस्सा है, जिसमें लौह अयस्क पेलेट्स की स्थिर और सस्ती उपलब्धता सुनिश्चित करना शामिल है।

थ्रिवेनी पेलेट्स ओडिशा के जाजपुर में 6 मिलियन टन प्रति वर्ष (MTPA) क्षमता वाला अत्याधुनिक पेलेट प्लांट चलाती है, जो टाटा स्टील की कलिंगनगर और जमशेदपुर इकाइयों के निकट है। यह प्लांट उच्च गुणवत्ता वाले पेलेट्स का उत्पादन करता है, जो स्टील निर्माण में महत्वपूर्ण कच्चा माल है। सौदा पूरा होने पर टाटा स्टील को थ्रिवेनी पेलेट्स का पूर्ण नियंत्रण मिल जाएगा, जिससे आयात पर निर्भरता कम होगी।

टाटा स्टील के सीईओ और एमडी टी.वी. नरेंद्रन ने कहा, यह अधिग्रहण हमें लागत नियंत्रण और आपूर्ति सुरक्षा देगा। हमारा लक्ष्य 2030 तक 40 MTPA स्टील उत्पादन है, जिसमें स्थानीय कच्चा माल 80% तक होगा। यह सौदा 2026 की पहली तिमाही में पूरा होने की उम्मीद है, जिसमें नियामक मंजूरी शामिल है। थ्रिवेनी अर्थमूवर्स के प्रमोटर इस प्लांट को 2022 में स्थापित किया था। टाटा स्टील ने पिछले वर्षों में कई खनन और प्रोसेसिंग कंपनियों में निवेश किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम स्टील क्षेत्र में लागत दबाव को कम करेगा। टाटा स्टील के शेयर 1.8% चढ़े। यह अधिग्रहण आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करेगा।

INVESTMENT AVENUES®

Looking To Invest In Real Properties & Valued Businesses In BhopaL

Discover genuine real estate and well-assessed business opportunities — safe-to-invest and growth-oriented.

Secure Deals. Smart Investments.

EMAIL: INVESTMENTAVENUES90@GMAIL.COM
CONTACT: +91 73899 26586

WEEKLY STOCK PIVOT LEVEL

Anil Bhardwaj
Technical Head
anil.stockcare@gmail.com

AII level indicated above are based on future prices PP: Pivot Point: This is TRIGGER POINT for buy/sell Based on the price range of the previous Month, R1: Resistance one: 1st Resistance over PP; R2: resistance Two: 2nd Resistance over R1; S1: Support one: 1st support after PP; S2: Support Two: 2nd support after S1

• As per tool, trader should take Buy position just above pp and keep the stop loss of PP and 1st target would be R1
• If R1 is crossed then R2 becomes the next target with the stop loss at R1
• If R2 is crossed then R3 becomes the next target with the stop loss at R2.
• Similarly, if price goes below PP the trader should SELL price below PP as stop loss and the first target would be S1,
• If S1 is crossed then S2 becomes the next target with the stop loss at S1,
• If S2 is crossed then S3 becomes the next target with the stop loss at S2.

Stock name	losing Rat	R3	R2	R1	PP	S1	S2	S3
NIFTY	26047	26735	26456	26252	25973	25769	25490	25286
BANK NIFTY	59390	60700	60204	59797	59301	58894	58398	57991
SENSEX	85268	87476	86589	85928	85041	84380	83493	82832
FINNIFTY	27673	28415	28138	27905	27628	27395	27118	26885
MIDCAP	13908	14691	14371	14140	13820	13589	13269	13038
ACC	1771	1841	1826	1799	1784	1757	1742	1715
AXISBANK	1285	1323	1307	1296	1280	1269	1253	1242
ABCAPITAL	363	386	378	370	362	354	346	338
BHARTIARTL	2082	2194	2154	2118	2078	2042	2002	1966
BHEL	284	312	300	292	280	272	260	252
BIOCON	385	414	404	395	385	376	366	357
CDSL	1524	1679	1623	1573	1517	1467	1411	1361
DATAPATTERN	2598	2991	2879	2738	2626	2485	2373	2232
ESCORTS	3655	3890	3815	3735	3660	3580	3505	3425
EICHERMOTOR	7230	7626	7475	7353	7202	7080	6929	6807
FEDERAL BANK	261	274	269	265	260	256	251	247
GRINFRAPOJECT	1016	1148	1111	1064	1027	980	943	896
HDFCBANK	1001	1031	1018	1010	997	989	976	968
HCLTECH	1670	1740	1717	1694	1671	1648	1625	1602
HINDUNILVR	2264	2430	2390	2327	2287	2224	2184	2121
HAL	4293	4684	4564	4428	4308	4172	4052	3916
HYUNDAI	2342	2472	2411	2377	2316	2282	2221	2187
IOC	164	174	171	167	164	160	157	153
ICICIBANK	1366	1432	1413	1390	1371	1348	1329	1306
INFY	1598	1674	1652	1625	1603	1576	1554	1527
ITC	401	409	407	404	402	399	397	394
KOTAKBNK	2177	2314	2260	2218	2164	2122	2068	2026
LICHOUSING	532	571	558	545	532	519	506	493
LT	4073	4292	4200	4136	4044	3980	3888	3824
LUPIN	2112	2220	2169	2140	2089	2060	2009	1980
MARUTI	16515	17327	16932	16723	16328	16119	15724	15515
M&M	3679	3852	3788	3734	3670	3616	3552	3498
MGL	1123	1243	1206	1165	1128	1087	1050	1009
MAZGAONDOC	2457	2788	2702	2579	2493	2370	2284	2161
PFC	344	371	362	353	344	335	326	317
RECLTD	344	370	362	353	345	336	328	319
RELIANCE	1554	1608	1584	1569	1545	1530	1506	1491
SBIN	963	995	984	973	962	951	940	929
SUNPHARMA	1794	1857	1834	1814	1791	1771	1748	1728
SHRIRAMFINANCE	849	907	883	866	842	825	801	784
TITAN	3871	4064	3980	3925	3841	3786	3702	3647
TCS	3220	3371	3315	3267	3211	3163	3107	3059
TATAMOTORS	347	370	363	355	348	340	333	325
UPL	747	793	777	762	746	731	715	700
VALIENT	273	304	291	282	269	260	247	238
WIPRO	261	270	266	264	260	258	254	252

एचडीएफसी डिफेंस फंड ने भारत डायनामिक्स समेत 4 कंपनियों में हिस्सेदारी बढ़ाई

नवंबर में 1.5% से अधिक स्टेक वृद्धि, डिफेंस सेक्टर में 20,000 करोड़ AUM; मेक इन इंडिया और निर्यात को मिलेगा बल

भोपाल: एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के डिफेंस फंड ने नवंबर में भारत डायनामिक्स लिमिटेड (BDL) और तीन अन्य डिफेंस कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी में उल्लेखनीय वृद्धि की है। नवंबर 2025 के शेयरहोल्डिंग पैटर्न के अनुसार, फंड ने BDL में 1.5% से अधिक स्टेक बढ़ाया, जबकि अन्य कंपनियों में भी 1-2% की बढ़ोतरी हुई। यह कदम भारत के डिफेंस सेक्टर में बढ़ते निवेश और 'मेक इन इंडिया' पहल को दर्शाता है।

एचडीएफसी डिफेंस फंड, जो जून 2024 में लॉन्च हुआ था, अब 20,000 करोड़ रुपये से अधिक AUM वाला हो गया है। फंड का पोर्टफोलियो BDL, HAL, BEL और मझगांव डॉक जैसे प्रमुख डिफेंस PSU पर केंद्रित है। BDL में फंड की हिस्सेदारी 4.8% से बढ़कर 6.3% हो गई। फंड मैनेजर अभिषेक पांडेय ने कहा, सरकार का 5 लाख करोड़ का डिफेंस बजट और निर्यात लक्ष्य 50,000 करोड़ तक ले जाने से सेक्टर में लंबी अवधि की वृद्धि सुनिश्चित है।

BDL, जो मिसाइल और टॉरपीडो बनाती है, हाल ही में 12,000 करोड़ के ऑर्डर हासिल कर चुकी है। फंड ने HAL और BEL में भी हिस्सेदारी बढ़ाई। विशेषज्ञों का मानना है कि डिफेंस फंड्स में इनफ्लो 2026 में 30,000 करोड़ पार कर सकता है। एचडीएफसी डिफेंस फंड ने लॉन्च से अब तक 45% रिटर्न दिया है। शेयर बाजार में BDL के शेयर 2.5% चढ़े। यह निवेश आत्मनिर्भर भारत के डिफेंस विजन को मजबूत करेगा।

HDFC
MUTUAL FUND
DEFENCE FUND

Disclaimer: This content is for educational purposes only. Investments are subject to market risks. Please conduct your own research or consult a qualified financial advisor before making any investment decisions.Investments are subject to market risks. Please conduct your own research or consult a qualified financial advisor before making any investment decisions.

प्रकाशक एवं मुद्रक: प्रदीप कारबेलकर, सी-101, नेहरू नगर स्वत्वाधिकार द इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज प्रा.लि., इ-4, अरेरा कॉलोनी, भोपाल, मध्य प्रदेश 462016, से प्रकाशित एवं DigitalLok, सागर हाई स्ट्रीट, अयोध्या बायपास रोड, डी मार्ट के पास, भोपाल, (म.प्र.) - 462010। संपादक: प्रदीप कारबेलकर (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)। फोन: +9198262 23075 वेबसाइट: www.investmentavenues.in